www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष – 05 | अंक – 78 | जौनपुर, मंगलवार, 03 नवम्बर 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

बांग्लादेश में कपड़ा मजदूरों के प्रदर्शन से ठप हुआ कामकाज

बांग्लादेश, (एजेंसी)। कपड़ा उद्योग के मजदूरों के हिंसक आंदोलन के बाद न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए सरकार ने एक छह–सदस्यीय वेज बोर्ड के गठन का एलान कर दिया है. लेकिन मजदूरों की नाराजगी और असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है. कपड़ा मजदूरों में न्यूनतम मजदूरी को लेकर असंतोष की आहट तो लंबे समय से मिल रही थी लेकिन शनिवार को अचानक हजारों मजदूर न्यूनतम मजदूरी मौजूदा साढ़े बारह हजार टका से तीस हजार टका प्रति माह करने की मांग में सड़कों पर उतर आए और हिंसक प्रदर्शन और आगजनी शुरू कर दी. राजधानी ढाका और आसपास के इलाकों में हालात इतने बिगड़ गए कि इस पर काबू पाने के लिए सरकार को अर्धसैनिक बल के जवानों को मैदान में उतारना पड़ा.सोमवार को प्रदर्शन के तीसरे दिन हालांकि कुछ फैक्ट्रियों में मजदूर काम पर वापस लौट आए हैं. लेकिन जगह–जगह विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है. सत्ता संभालने के बाद से ही तमाम समस्याओं से जूझ रही तारिक रहमान सरकार के लिए यह आंदोलन एक नया सिरदर्द बन गया है. देश की अर्थव्यवस्था के लिए कपड़ा उद्योग बहुत अधिक अहमियत रखता है।

एक सूत्र में पिरोती है साझी आस्था और संस्कृति - सीएम योगी



लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि जाति की जड़ता समाज को बांटने का काम करती है, वहीं साझा आस्था और संस्कृति समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। उन्होंने श्री अयोध्या जी के दीपोत्सव को इसी सामाजिक एकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले, जातीय विभाजन को राजनीति का आधार बनाने वाली सरकारों ने समाज को जोड़ने वाली सांस्कृतिक शक्ति की उपेक्षा की। इसके विपरीत, डबल इंजन सरकार ने वर्ष 2017 में दीपोत्सव की शुरुआत करके इस सोच को बदला और राम नगरी की सांस्कृतिक विरासत को एक बड़े जन–जन के उत्सव में परिवर्तित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे लिखा कि पूज्य संतगण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, आज के दीपोत्सव आयोजन में धर्माचार्य, विद्यार्थी, स्वच्छताकर्मी, कुम्हार और व्यापारी सभी समान उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लेते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यहां पहचान जाति से नहीं, बल्कि सहभागिता से होती है। दीप भले ही अलग–अलग हाथों में जलते हैं, लेकिन उनका प्रकाश पूरे समाज को एक करता है। यही दीपोत्सव का संदेश है और यही समरस समाज की संकल्पना है।उन्होंने दीपोत्सव को जनभागीदारी वाला उत्सव बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने अयोध्या के लोगों से अपने घरों और प्रतिष्ठानों में दीप जलाकर इस आयोजन में भाग लेने की अपील की। बैठक में जनप्रतिनिधियों और मंडलायुक्त सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। रामकथा पार्क के पास बने हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा, जहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे रामकथा पार्क पहुंचे और दीपोत्सव से जुड़े विभिन्न कार्यों का मौके पर निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।

नितिन गडकरी से मिले सम्राट चौधरी, बिहार की चार राजमार्ग परियोजनाओं के लिए मांगी अंतिम मंजूरी

पटना, (एजेंसी)। दो नवंबर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य में 49,751 करोड़ रुपये की लागत वाली चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग एवं एक्सप्रेस–वे परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने का उनसे अनुरोध किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, दिल्ली दौरे में गडकरी के आवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने बिहार में सड़क संपर्क, एक्सप्रेस–वे निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने राज्य में सड़क एवं बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगातार सहयोग देने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गडकरी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 330 किलोमीटर लंबाई वाली चार प्रमुख परियोजनाओं को भारत सरकार की सार्वजनिक–निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) से मंजूरी मिल चुकी है। ये परियोजनाएं फिलहाल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की अंतिम स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं। इनमें 1,976.77 करोड़ रुपये की लागत से गंडक नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग–727एए के तहत दो लेन वाले पुल और संपर्क मार्ग का निर्माण शामिल है। यह पुल बिहार के मनुआपुल (बेतिया) को उत्तर प्रदेश के तिवारीपट्टी (सेवराही) से जोड़ेगा। इसके अलावा, 8,455.86 करोड़ रुपये की लागत से सरिस्ताबाद–दीदारगंज और अनीसाबाद–दीदारगंज खंड में छह लेन वाले एलिवेटेड मार्ग और सर्विस रोड का निर्माण किया जाना है।



राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में रक्षा पैनल की बैठक में दिया जोर, कहा– 'आधुनिक युद्ध के लिए आधुनिक सेना जरूरी'

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, तीनों सेनाओं के उप–प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद मौजूद रहे। इनमें तरुण चुघ, संदीप पाठक, पवन खेड़ा, तिरुचि शिवा, सुदीप बंद्योपाध्याय, सौगत रॉय और नवीन जिंदल शामिल थे। अपनी शुरुआती टिप्पणी में रक्षा मंत्री ने कहा, "आज की बैठक का मुख्य फोकस सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों ने हमारी सुरक्षा प्राथमिकताओं को और महत्वपूर्ण बना दिया है। ड्रोन, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। हमारी सेना को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।"आधुनिकीकरण के तीन मुख्य स्तंभराजनाथ सिंह ने आधुनिकीकरण के तीन अहम स्तंभ बताए उन्होंने बताया कि हर साल आधुनिकीकरण बजट बढ़ाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए कुल रक्षा बजट 7.85 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें से 2.19 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च और उपकरणों की खरीद के लिए आवंटित किए गए हैं। रुपये से कम था, जो अब लगभग 40,000 करोड़ रुपये हो चुका है। 2029 तक उत्पादन 3 लाख करोड़ और निर्यात 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री ने कहा कि तकनीक अब युद्ध का अभिन्न अंग बन चुकी है। डीआरडीओ नई योजनाएं चला रहा है और नए हथियार–मिसाइल सिस्टम का परीक्षण हो रहा है। निजी क्षेत्र को समान अवसर देकर एमएसएमई से लेकर बड़ी कंपनियों तक को प्रोत्साहित किया जा रहा है।



दीपोत्सव में दिखेगा जेन-जी का अंदाज,रामायण के प्रसंगों का होगा आधुनिक तकनीक से प्रदर्शन

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।रामनगरी में सात नवंबर को आयोजित होने वाला दसवां दीपोत्सव इस बार जेन–जी यानी नई पीढ़ी के आधुनिक अंदाज में नजर आएगा। राम की पैड़ी पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से करीब 28 मिनट का भव्य मल्टीमीडिया एवं लेजर शो आयोजित किया जाएगा। इसमें 100 से अधिक भारतीय लोक एवं शास्त्रीय कलाकार भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन की गाथा को जीवंत करेंगे।शो में प्रोजेक्शन मैपिंग, 2डी–3डी विजुअल, लेजर लाइट और एरियल एक्ट के माध्यम से रामायण के प्रमुख प्रसंगों का प्रदर्शन होगा। इसके लिए राम की पैड़ी पर पानी के बीच फ्लोटिंग मंच तैयार किया जा रहा है, जहां कलाकार लाइव प्रस्तुति देंगे। नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए रामायण के पांच प्रसंगों को 3डी तकनीक के जरिए मोबाइल पर देखने की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए आईओएस और एंड्रॉयड ऐप तैयार किया जाएगा। दर्शक मोबाइल से निर्धारित स्थान स्कैन कर ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) तकनीक के माध्यम से रामायण के दृश्य देख सकेंगे और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा भी कर सकेंगे।आयोजन के तहत पांच नवंबर को दो ट्रायल शो, छह नवंबर को फुल ड्रेस रिहर्सल और सात नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष विशेष प्रस्तुति होगी। आठ नवंबर को दीपावली के दिन चार शो आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आठ मिनट का लेजर शो और 20 मिनट का प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी आकर्षण का केंद्र रहेगा।वहीं,अयोध्या वासियों के लिए नौ नवंबर को विशेष ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा।पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक, इस आयोजन का उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से नई पीढ़ी को रामनगरी की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जोड़ना है।





संपादकीय

इंटरनेट बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं

अदालत ने स्वीकार किया इंटरनेट की वर्तमान स्थिति बच्चों के लिए कतई सुरक्षित नहीं है। यह मानने के बावजूद जजों ने सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी चाइल्ड मोड की सुविधा और माता–पिता की निगरानी पर डाल दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बच्चों को भी बालिगों की तरह इंटरनेट के उपयोग का अधिकार है। श्सुरक्षाच्य के नाम पर इंटरनेट तक उनकी पहुंच रोकी नहीं जा सकती। इस रूप में कोर्ट ने आधुनिक जीवन में इंटरनेट के महत्त्व को रेखांकित किया है। यह सराहनीय है कि कोर्ट ने प्रतिबंध ही सुरक्षा है, जैसी प्रशासनिक सोच को खारिज कर दिया। दरअसल, बच्चों को साइबरस्पेस से बाहर निकालना पीड़ित को ही समस्या मान लेने जैसा है। उचित ही न्यायालय ने इस नजरिए को ठुकरा दिया। इसके बावजूद इस फैसले में कई समस्याएं हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खुद अदालत ने स्वीकार किया इंटरनेट की वर्तमान स्थिति बच्चों के लिए कतई सुरक्षित नहीं है। यह मानने के बावजूद जजों ने सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी चाइल्ड मोड की सुविधा और माता–पिता की निगरानी पर डाल दी। यानी सेवा प्रदाता प्लेटफॉर्म कंपनियों को जवाबदेही से पूरी तरह मुक्त कर दिया। कोर्ट ने इन कंपनियों से बाल यौन शोषण सामग्री हटाने को कहा तो है, लेकिन उनके अनिवार्य तकनीकी ऑडिट और सजा का कोई प्रावधान नहीं किया। अदालत की यह राय वाजिब है कि दूरदराज के इलाकों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पास अक्सर सीखने और दुनिया से जुड़ने का एकमात्र माध्यम इंटरनेट ही होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में प्लेटफॉर्म कंपनियों की जवाबदेही तय करने का सिस्टम और जरूरी हो जाता है। गरीब परिवारों में माता–पिता अक्सर डिजिटल साक्षर नहीं होते। उनके बच्चे सस्ते स्मार्टफोन के जरिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। डिवाइस सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, और सामग्री फिल्टरिंग के अभाव में इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार किस हद तक सशक्तीकरण है, यह सवाल बना रहेगा। वैसे भारत में व्यापक दायरे में भी अधिकार और उसके उपभोग की स्थितियों ने एक विरोधाभास खड़ा कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट पहले निर्णय दे चुका है कि बार–बार इंटरनेट शट–डाइन नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन इससे शटडाउन पर रोक नहीं लगी है। भारत सबसे ज्यादा ऐसा शट–डाउन करने वाला देश बना हुआ है। इसीलिए अधिकार की हर न्यायिक घोषणा के व्यावहारिक महत्त्व पर अक्सर नया सवाल उठ खड़ा होता है।

एमएलसी चुनाव के निहितार्थ

देश के चार राज्यों उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में विधानपरिषद की 28 सीटों के लिए चुनाव हुए। जिस के नतीजों से इस समय सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि विधानपरिषद के चुनाव विधानसभा चुनावों से अलग होते हैं। इसमें जनता सीधे मतदान नहीं करती, बल्कि उसके द्वारा चुने प्रतिनिधि मतदान करते हैं। विधानपरिषद के सदस्य यानी एमएलसी छह सालों के लिए निर्वाचित होते हैं और सबसे बड़ी बात ये चुनाव मतपत्रों से होते हैं। मतलब चुनावी राजनीति का एमएलसी चुनाव से सीधे कोई लेना–देना नहीं है। लेकिन जब पंचायत से लेकर स्थानीय निकाय तक के चुनावों में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सीधी दिलचस्पी रहती है, तो फिर एमएलसी चुनाव भी आम चुनावों जैसी हलचल मचा देते हैं।हालांकि 28 सीटों के जो नतीजे आए हैं, उन पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरु हो चुकी है। दरअसल बुधवार को जब नतीजे आ ही रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक पोस्ट आ गई, जिसमें कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा– चुनाव बैलेट पेपर से हुए तो अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं। और इसके साथ एक इमोजी भी डाला है। इस पोस्ट के बाद सवाल उठने लगे कि किसी पार्टी की हार या जीत अपनी जगह है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी पद की गरिमा भूलकर अब ट्रोलर्स की तरह बातें करने लगेंगे। मोदी की इस पोस्ट को ही आगे बढ़ाते हुए अमित शाह और देवेन्द्र फड़नवीस ने भी बिना देर किए अपनी तरफ से कांग्रेस के लिए शून्य सीटों का जिक्र कर मजे लिए। लेकिन अब उनका यह फूहड़ता से मजा लेना, भाजपा पर ही भारी पड़ चुका है। यह सही है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, और फिर भी वहां उसे एमएलसी चुनाव में जीत नहीं मिली। लेकिन भाजपा ने जो सीटें हारी हैं, वो कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ी जीत है। कांग्रेस कर्नाटक में हारी, मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुख्यालय, देवेन्द्र फड़नवीस और नितिन गडकरी का गृहनगर नागपुर उसके खाते में आया है। नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। उन्होंने 2020 में पहली बार यह सीट जीती थी और अब 2026 में भी इसे अपने पास बनाए रखा है। बकौल संजय राउत कांग्रेस की यह एक सीट बीजेपी के लिए सौ सीटों के बराबर है। पुणे और औरंगाबाद की स्नातक सीटों पर शरद पवार की एनसीपी ने जीत दर्ज की है। यानी तीन सीटों पर महाविकास अगाड़ी जीती है।भाजपा के लिए एक बड़ा झटका नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी आया है। यहां के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र दोनों में सपा की जीत हुई है। लखनऊ भी भाजपा हार चुकी है। उप्र की 11 सीटों में भाजपा के खाते में छह और सपा के खाते में पांच सीटें आई हैं। वहीं बिहार की आठ सीटों में तीन पर भाजपा, एक पर जदयू, राजद और जनसुराज को एक–एक और निर्दलीयों को 2 सीटें मिली हैं। राजद के लिए यह जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि नितिन नबीन के पटना क्षेत्र पर उसने भाजपा को मात दी है।इस तरह देखें तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक मुख्यमंत्री के क्षेत्र में विपक्ष ने जीत हासिल की है। फिर भी प्रधानमंत्री अगर यह बता रहे हैं कि बैलेट पेपर यानी मतपत्रों से चुनाव में भी जीत भाजपा की हुई है, तो फिर उन्हें अविलंब देश में ईवीएम की जगह मतपत्रों का इस्तेमाल शुरु करने की पहल करना चाहिए या फिर एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसे हर चुनाव में जो मन में आए, वो हांकने से बचना चाहिए।जैसा कि पहले जिक्र किया गया, विधानसभा और विधानपरिषद के चुनावों में, एमएलए और एमएलसी की जिम्मेदारियों और अधिकारों में काफी फर्क होता है। विधान परिषद् विधानसभा का उच्च और स्थायी सदन है। यानी यह कभी भंग नहीं होता। विधान परिषद की लगभग एक–तिहाई सीटों पर स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि मतदान करते हैं। इनमें नगर निगम, नगरपालिका और जिला स्तर के संबंधित स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आम जनता की जगह निर्धारित निर्वाचक मंडल के सदस्य मतदान करते हैं। वहीं विधान परिषद की लगभग एक–बारहवीं सीटें स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होती हैं और लगभग इतनी ही सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्धारित हैं। इसके अलावा विधान परिषद की लगभग एक–तिहाई सीटों पर राज्य के विधायक मतदान करते हैं। विधानसभा के सदस्य एमएलसी उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के क्रम में वोट देते हैं। और फिर विधान परिषद के बाकी सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। संविधान के अनुसार, ऐसे लोगों को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।जैसे उत्तरप्रदेश विधानपरिषद में कुल सौ सदस्यों की जगह है, तो सारे विधायक 38 सदस्यों को चुनते हैं, स्थानीय निकायों द्वारा चुने गए सदस्य 36 होते हैं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से 8 सदस्य, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से 8 सदस्य और राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य 10 होते हैं।

भूटान की पहाड़ियों से उठी जलप्रलय की आहट, आपदा से निबटने के लिए भारत कितना तैयार है

नीरज

हिमालय की बर्फीली चोटियों से उठी एक प्राकृतिक हलचल ने भारत के पूर्वोत्तर और उत्तर बंगाल की चिंता बढ़ा दी है। भूटान की शिंताफू ग्लेशियर झील के फटने से निकला पानी नदियों के रास्ते भारत की ओर बढ़ा। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया, गांव खाली कराए गए और बचाव एजेंसियों को मोर्चे पर लगाया गया। फिलहाल पानी का स्तर घटने के संकेत हैं, लेकिन एक नई अस्थायी झील बनने से खतरे का एक और पहलू सामने आ गया है। दरअसल, हिमालय की ऊंची चोटियों पर जमा बर्फ जब टूटती है, तो उसका असर केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं रहता। कई बार हजारों फीट नीचे बसे गांवों, कस्बों और शहरों की जिंदगी भी इसकी चपेट में आ जाती है। भूटान में 29 अक्टूबर 2026 को हुई ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटना ने एक बार फिर इसी खतरे की गंभीरता को सामने ला दिया है। हम आपको बता दें कि भूटान के गासा जिले के लेमथांग क्षेत्र में स्थित शिंताफू झील के बांधनुमा प्राकृतिक अवरोध के टूटने से भारी मात्रा में पानी बाहर निकला। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार, कूचबिहार और असम के धुबरी तथा कोकराझार जिलों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन को सतर्क कर दिया गया। केंद्रीय जल आयोग ने भी संभावित जलस्तर वृद्धि को लेकर विशेष बाढ़ परामर्श जारी किया। अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र के अनुसार, घटना से पहले शिंताफू झील में लगभग 60 से 70 लाख घन मीटर पानी मौजूद था। यह करीब 2,400 से 2,800 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल के बराबर है। हालांकि, वास्तव में कितना पानी बाहर निकला, इसका आकलन अभी किया जा रहा है। इस पानी का प्रवाह भूटान की मो छू नदी और आगे पुनात्सांगछू नदी तंत्र से होते हुए भारत में संकोश नदी की ओर बढ़ा। भारत में संकोश नदी पश्चिम बंगाल और असम के सीमावर्ती इलाकों के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, पानी को सीमा तक पहुंचने में लगभग छह से आठ घंटे लगने की आशंका जताई गई थी। यही वजह रही कि प्रशासन ने संभावित खतरे को गंभीरता से लेते हुए पहले ही सतर्कता बढ़ा दी। उधर, पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लगभग 6,000 से 7,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इनमें नदी किनारे और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले परिवार शामिल थे। राहत शिविरों में चार हजार से अधिक लोगों के लिए भोजन, राशन, बच्चों के लिए जरूरी खाद्य सामग्री और दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई। जलपाईगुड़ी और कूचबिहार में भी निगरानी बढ़ाई गई। प्रशासन ने लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को नदी किनारों और निचले इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी। नागरिक सुरक्षा की टीमें तैनात की गईं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने धुबरी और कोकराझार के संवेदनशील राजस्व क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और साथ लगातार संपर्क बनाए रखने तथा लोगों से सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक संकोश नदी का जलस्तर घटने लगा है। कोकराझार के जिला प्रशासन ने भी तत्काल बड़े पैमाने पर जलभराव की आशंका कम होने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं है। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे चिंताजनक तथ्य एक नई अस्थायी झील का निर्माण है। भूटान के राष्ट्रीय जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, पानी और मलबे के बहाव से टाक्त्सेमाखांग में एक नई झील बन गई है। यह सिंताफू छू और लुंगू छू नदियों के संगम के पास स्थित है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी अस्थायी झीलें दोबारा बाढ़ का कारण बन सकती हैं। तेज बहाव अपने साथ चट्टानें और मलबा लाता है, जिससे नदी का रास्ता अवरुद्ध हो सकता है। यदि पानी का दबाव बढ़कर इस प्राकृतिक अवरोध को तोड़ता है, तो दूसरी बाढ़ पैदा हो सकती है। इसलिए भूटान में मो छू और पुनात्सांगछू नदी घाटियों के आसपास रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यहां सवाल उठता है कि आखिर क्यों फट रही हैं हिमालय की ग्लेशियर झीलें? देखा जाये तो इसका सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और तेजी से पिघलते ग्लेशियरों को माना जाता है। ग्लेशियरों के पीछे हटने से उनके आसपास बड़ी–बड़ी झीलें बनती हैं। इनमें पानी अक्सर बर्फ, चट्टानों और हिमनदों से निकले मलबे के प्राकृतिक बांधों के पीछे जमा होता है। भारी बारिश, हिमस्खलन, चट्टानों का झील में गिरना, भूकंप और प्राकृतिक बांधों का कमजोर होना अचानक पानी के बाहर निकलने का कारण बन सकते हैं। इसी घटना को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ळस्ब् कहते हैं। यह सामान्य बाढ़ से अधिक खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसमें पानी के साथ भारी मात्रा में पत्थर, मिट्टी और मलबा भी तेजी से नीचे आता है। देखा जाये तो भूटान की यह घटना भारत के लिए केवल एक स्थानीय बाढ़ का मामला नहीं है। यह हिमालयी राज्यों की आपदा प्रबंधन व्यवस्था की भी परीक्षा है। भारत सरकार ने सितंबर 2026 में हिमालयी राज्यों की हिमस्खलन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की थी। इसमें शुरुआती



चेतावनी प्रणाली, संवेदनशील झीलों की निगरानी, जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान और समय पर लोगों को सुरक्षित निकालने पर जोर दिया गया था। लेकिन अब कुछ सवालों के जवाब तलाशना जरूरी है। सवाल उठता है कि क्या भूटान और भारत के बीच ग्लेशियर झीलों के जलस्तर की वास्तविक समय में जानकारी साझा करने की व्यवस्था पर्याप्त है? क्या असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर बंगाल के सभी संवेदनशील नदी तटीय गांवों तक समय रहते चेतावनी पहुंचाने का तंत्र मौजूद है? क्या नदियों पर बने बांधों और जलविद्युत परियोजनाओं की ळस्ब् जैसी अचानक आने वाली बाढ़ से निपटने की क्षमता का नियमित परीक्षण हो रहा है? क्या प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित आश्रय स्थल, निकासी मार्ग और प्रशिक्षित बचाव दल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं? क्या नई अस्थायी झील की लगातार निगरानी और उसके संभावित टूटने की स्थिति में दूसरी चेतावनी जारी करने की व्यवस्था तैयार है? बहरहाल, सबसे बड़ी जरूरत सीमा पार समन्वय, वैज्ञानिक निगरानी और जमीनी स्तर पर तैयारी की है। भूटान में हुई घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि हिमालय की चोटियों पर पैदा होने वाला खतरा किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं पहचानता। आज पानी का स्तर घट रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के दौर में ऐसी घटनाएं भविष्य में और गंभीर हो सकती हैं। इसलिए प्रशासन के लिए असली चुनौती बाढ़ आने के बाद राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि बाढ़ आने से पहले हर संभावित खतरे को पहचानकर लोगों की जिंदगी बचाना है।

दस दिन में चार चुनाव – तानाशाही को आखिरकार मिल रहा है जवाब

नित्य

स्टूडेंट स्ट्रीट पिछले 14 सालों में वुसिक शासन के तानाशाही रवैए को खत्म करके देश को असली लोकतंत्र में बदलने के लिए 11सूत्री योजना पर काम कर रहा है। नए युवा नेता कह रहे हैं कि वे लोकतांत्रिक अधिकारों और संस्थानों के काम करने को पारदर्शी तरीके से पक्का करेंगे। जैसा कि एक लीडर ने समझाया कि पहला काम देश का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषमुक्तिकरण होना चाहिए। इस साल 25 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच सिर्फ दस दिनों में, चार राष्ट्रीय चुनाव तय थे। इनमें से, ब्राजील और सर्बिया में 25 अक्टूबर को और इजराइल में 27 अक्टूबर को चुनाव हुए। सिर्फ 3 नवंबर को, संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होंगे। सत्तारूढ़ रिपब्लिकन और विपक्षी डेमोक्रेट के बीच कड़वाहट से भरा चुनाव अभियान अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है, जिसमें सभी जनमत सर्वेक्षणों में डेमोक्रेट पार्टी को बढ़त मिली है। अब तक आये तीनों चुनाव नतीजों में तानाशाही के खिलाफ एक पक्का संदेश है। ब्राजील में, रविवार रात को चुनाव के घोषित अंतिम नतीजे, लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अमेरिका का उपनिवेश बनाने के इरादे वाले घोर दक्षिणपंथी उम्मीदवार फ्ल्वियो बोल्सोनारो के कदमों के खिलाफ ब्राजील के लोगों की प्रभुसत्ता की पुष्टि थे। ब्राजील के मतदाताओं ने उनकी योजना को पूरी तरह से नाकाम कर दिया और वाम गठबंधन के उम्मीदवार लूला को अगले चार साल के लिए सत्ता सौंप दी, जिससे वे चौथी बार राष्ट्रपति बन गए।फ्लेवियो बोल्सोनारो ने अब अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ अमेरिका में शरण ले ली है। उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है, लेकिन जेल में बंद उनके पिता पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो से फर्क यह था कि सीनियर बोल्सोनारो 2022 के राष्ट्रपति चुनावों में अपनी हार के बाद भी ब्राजील में ही रहे और विद्रोह करने की कोशिश की। वे नाकाम रहे और सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें देशद्रोह के लिए 27 साल की जेल की सजा सुनाई। फ्लेवियो बोल्सोनारो के अमेरिका में बसने का तुरंत नतीजा ब्राजील के अति दक्षिणपंथी शाखा में निराशा है। अब कोई भी असरदार अति दक्षिणपंथी नेता नहीं है जो राष्ट्रपति लूला का मुकाबला कर सके। अति दक्षिणपंथी शाखा ने पहले चक्र में अच्छा प्रदर्शन किया और हाउस ऑफ डेप्युटीज में बहुमत और सीनेट में दो–तिहाई सीटें हासिल की। दोनों सदनों में बोल्सोनारो परिवार के बहुत सारे चुने हुए सदस्य हैं। लेकिन ब्राजील में अति दक्षिणपंथी शाखा का नेतृत्व संभालने के लिए किसी को भी काबिल नहीं माना जा रहा है।ब्राजील में सत्तारूढ़ गठबंधन अब जोश में है और काफी सक्रियता दिखा रहा है क्योंकि दो दूसरी दक्षिणपंथी पार्टियां, जिन्होंने चुनावों में बोल्सोनारो को समर्थन दिया था, फ्लेवियो के अमेरिका से ब्राजील की राजनीति चलाने के फैसले से दूरी बना रही हैं। अभी तक, ब्राजील में अति दक्षिणपंथी निराश हैं। अब यह राष्ट्रपति लूला और वाम गठबंधन पर निर्भर करेगा कि सरकार आम लोगों के लिए अपने प्रस्तावित कार्यक्रम को कैसे लागू करती है और राष्ट्रीय राजनीति में अति दक्षिणपंथियों को और अलग–थलग कैसे करती है। ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम ने अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर जैसे दूसरे देशों में वाम को तानाशाह ट्रंप समर्थक सरकारों के खिलाफ अपने संघर्ष को तेज करने के लिए नयी ऊर्जा दी है।जहां तक यूरोप के एक छोटे से देश सर्बिया का सवाल है, जो पहले के यूगोस्लाविया के बंटवारे से बना है, रविवार के राष्ट्रीय चुनाव के परिणाम जैसे आये वैसे पहले कभी नहीं हुए थे। विरोध करने वाले स्टूडेंट और युवा जो 14 साल पुराने एलेक्जेंडर वुसिक सरकार से लड़ रहे थे, ने स्टूडेंट स्ट्रीट पार्टी के बैनर तले एक साथ आकर 250 सदस्यों वाली संसद



में 140सीटें जीत कर वुसिक सरकार को आसानी से हरा दिया। यह ग्रुप असल में ऐसी जीत और सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए एक नेता के साथ एक कोर टीम बनाने के लिए बातचीत चल रही है। सर्बिया के विरोध प्रदर्शन और आखिरकार सत्ता पर कब्जा करने में नेपाल और बांग्लादेश के घटनाक्रमों से मिलती–जुलती बातें हैं, लेकिन फर्क यह है कि सर्बिया के स्टूडेंट और युवाओं ने वुसिक सरकार को नहीं गिराया, उन्होंने प्रोटेस्ट मीटिंग कीं, लेकिन उन्हें हटाने के लिए राष्ट्रीय चुनाव का इंतजार किया।स्टूडेंट स्ट्रीट पिछले 14 सालों में वुसिक शासन के तानाशाही रवैए को खत्म करके देश को असली लोकतंत्र में बदलने के लिए 11सूत्री योजना पर काम कर रहा है। नए युवा नेता कह रहे हैं कि वे लोकतांत्रिक अधिकारों और संस्थानों के काम करने को पारदर्शी तरीके से पक्का करेंगे। जैसा कि एक लीडर ने समझाया कि पहला काम देश का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषमुक्तिकरण होना चाहिए। सर्बियाई चुनाव में छात्र आन्दोलन की सफलता का असर फ्रांस, इटली, स्पेन और यहां तक कि पुर्तगाल सहित दूसरे देशों में चल रहे विरोध आन्दोलनों पर भी पड़ा है। फ्रांस में, छात्र आन्दोलन छह हफ्ते से ज्यादा समय से जारी हैं। मैक्रो सरकार ने अभी भी विरोध कर रहे छात्र नेताओं के साथ समझौते के लिए बातचीत नहीं की है। बल्कि सुरक्षा के उपाय और बढ़ा दिए गए हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव मई 2027 में होने हैं। मैरी ले पेन की घोर दक्षिणपंथी पार्टी और वाम पार्टी, दोनों ही आने वाले चुनावों के लिए विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। यह अभी भी साफ नहीं है कि फ्रांस में चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शनों से सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा। इजरायल में, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मुश्किल में हैं क्योंकि सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटों के मुकाबले उनके पास 53 सीटें हैं, इसलिए वह किसी भी तरह से अपनी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं। उनके विरोधी आइजेनकोट को 48 सीटें मिली हैं, लेकिन अरब पार्टियों के बीच उनकी ज्यादा स्वीकार्यता है, जिन्हें कुल मिलाकर 19 सीटें मिली हैं और वे गठबंधन सरकार बनाने के लिए फैच्सला लेने वाले के तौर पर उभरे हैं। आखिर में जो भी सरकार बनेगी, उसके लिए उन्हें अरब पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसका मतलब यह होगा कि फिलिस्तीनियों को लेकर इजरायल की मौजूदा नीति में काफी बदलाव करना होगा। नेतन्याहू के कार्यकाल के दौरान उनके तानाशाही रवैये को भी कम करना होगा। राष्ट्रपति ट्रम्प को भी अपनी इजरायल नीति के अनिश्चित भविष्य के लिए तैयार रहना होगा।

सतत सड़क बुनियादी ढांचे की दिशा में भारत की यात्रा

भारत का हरित राजमार्ग दृष्टिकोण वृक्षारोपण, जलवायु–अनुकूल डिजाइन और संसाधन–कुशल निर्माण के माध्यम से सड़क बुनियादी ढांचे में बदलाव ला रहा है। पिछले पांच वर्षों में, लगभग 1.32 लाख किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3.61 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। मियावाकी वनों से लेकर पुनर्चक्रित निर्माण सामग्री और स्वदेशी जैव–बिटुमेन प्रौद्योगिकी तक, हरित पद्धतियां राजमार्ग विकास को आकार दे रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक के माध्यम से उपग्रह–आधारित निगरानी हरित आवरण के वैज्ञानिक आकलन को मजबूत कर रही है। सामुदायिक पहल और परागणकर्ता गलियारे भी व्यापक पारिस्थितिक आयाम जोड़ रहे हैं। सड़कें बनाना, हरियाली बढ़ाना भारत के राजमार्ग अब केवल संपर्क के गलियारे नहीं रह गए हैं। वे देश के व्यापक बुनियादी ढांचे में हो रहे बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। जैसे–जैसे सड़क बुनियादी ढांचे का विस्तार हो रहा है, वैसे–वैसे ऐसे गलियारे विकसित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जो दक्ष, सुदृढ़ और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हों। पिछले एक दशक में, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़कर मार्च 2026 तक 1,46,572 किलोमीटर हो गया है। इस तेजी से हुए विकास ने संपर्क को मजबूत किया है, बाजारों तक पहुंच में सुधार किया है और लोगों तथा वस्तुओं की तेज आवाजाही में सहायता की है। जैसे–जैसे सड़क बुनियादी ढांचे का विस्तार हो रहा है, वैसे–वैसे ऐसे गलियारे विकसित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जो दक्ष, सुदृढ़ और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हों। राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के किनारे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, पुनर्चक्रित और अपशिष्ट से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग, ऊर्जा–कुशल निर्माण पद्धतियां तथा हरित आवरण की उपग्रह–आधारित निगरानी अधिक टिकाऊ राजमार्ग नेटवर्क के निर्माण में योगदान दे रही हैं। हरीत हाईवे नीति, 2015रू नीति का विकास भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को हरित बनाने का मार्गदर्शन हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रतिरोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव) नीति, 2015 द्वारा किया जाता है। इस नीति को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया थारू राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण के लिए एक नीतिगत ढांचा विकसित करना। वायु प्रदूषण और धूल के प्रभाव को कम करना, क्योंकि पेड़ और झाड़ियां वायु प्रदूषकों के प्राकृतिक अवशोषक के रूप में जानी जाती हैं। तटबंधों की ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकना। हवा और आने वाले विकिरण के प्रभाव को कम करना। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। नीति के कार्यान्वयन में कई हितधारक मिलकर काम करते हैं। स्वीकृत कार्यों के दायरे के अनुसार स्वयं सहायता समूहों, निजी एजेंसियों, राज्य वन विभागों, वन निगमों और ठेकेदारों द्वारा वृक्षारोपण गतिविधियां की जाती हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और अन्य एजेंसियों के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से समग्र निगरानी के लिए एक वृक्षारोपण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। गलियारों को हरित बनानारू वृक्षारोपण और वनीकरण राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने के प्रयासों को अब राजमार्ग गलियारों के किनारे लगाए गए पौधों की संख्या, उनके जीवित रहने, वृद्धि और वितरण के आधार पर तेजी से मापा जा रहा है। जुलाई 2026 तक, पिछले पांच वर्षों के दौरान लगभग 1.32 लाख किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3.61 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इस दृष्टिकोण का विस्तार अब केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यापक पर्यावरण प्रबंधन को भी शामिल किया गया है। पहले, वृक्षारोपण की निगरानी मुख्य रूप से क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा स्थल पर जाकर की जाती थी। आज, इसे ड्रोन और उपग्रह–आधारित निगरानी से भी मजबूत किया जा रहा है। हरित आवरण बढ़ाने के लिए मियावाकी वृक्षारोपण भी शुरू किया गया है। जहां राजमार्ग विकास के लिए पेड़ों की कटाई आवश्यक होती है, वहां क्षतिपूरक वनीकरण और पेड़ों का प्रतिरोपण किया जा रहा है। वृक्षारोपण और भूदृश्य निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास और परियोजना पूर्णता का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। एनएचएआई के सितंबर 2026 के दिशानिर्देश इस दृष्टिकोण को और मजबूत करते हैं। अनंतिम पूर्णता प्रमाणन के लिए वृक्षारोपण कार्य तभी अनुपालन योग्य माने जाएंगे, जब वृक्षारोपण के लिए निर्धारित उपलब्ध राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के कम से कम 80 प्रतिशत हिस्से को कवर किया गया हो। आरओडब्ल्यू से आशय उस निर्धारित भूमि क्षेत्र से है, जो राजमार्ग बुनियादी ढांचे के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए कानूनी रूप से आवश्यक होता है। निरीक्षण के समय लगाए गए पौधों की जीवित रहने की दर भी न्यूनतम 90 प्रतिशत होनी चाहिए। यही जीवित रहने का मानदंड संचालन और रखरखाव अवधि के दौरान भी लागू होगा तथा जो पौधे जीवित नहीं रह पाते हैं, उन्हें समय पर बदलने का प्रावधान होगा। अच्छी पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए एनएचएआई ने 2025 में ग्रीन हाईवेज एक्सीलेंस अवार्ड्स की शुरुआत की। 2026 के पुरस्कारों में पौधों के जीवित रहने को सबसे अधिक महत्व दिया गया, साथ ही प्रजातियों की विविधता, देशज प्रजातियों के उपयोग, स्थल–विशिष्ट योजनाओं और संरक्षण उपायों को भी महत्व दिया गया। भारत के राजमार्ग भी जीवाश्म ईंधन–आधारित सामग्रियों से हटकर जैव–आधारित, पुनर्योजी समाधानों की ओर बढ़ रहे हैं। जनवरी 2026 में कृषि अवशेषों के पायरोलिसिस के माध्यम से उत्पादित जैव–बिटुमेन की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलता की घोषणा की गई। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वैज्ञानिक निष्कर्षों, ज्ञान और बौद्धिक संपदा को विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से सार्वजनिक और निजी उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। पायरोलिसिस के माध्यम से जैव–बिटुमेनरू कृषि अवशेषों से सड़कों तक नामक इस नवाचार को सीएसआईआर–केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और सीएसआईआर–भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। बिटुमेन कार्बनिक द्रवों और हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, जिसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है और इसे सड़क निर्माण उद्योग में काला सोना कहा जाता है। वर्तमान में, भारत अपनी बिटुमेन आवश्यकता का लगभग 50 प्रतिशत आयात के माध्यम से पूरा करता है। जैव–बिटुमेन जैसे नवाचार आयात पर निर्भरता को कम करने के साथ–साथ घरेलू उत्पादन क्षमताओं को मजबूत कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में पायरोलिसिस के माध्यम से जैव–तेल के उत्पादन के लिए कटाई के बाद प्राप्त धान के पुआल का फीडस्ट

सांसों की माला में पिरोया आध्यात्मिकता और संस्कृति का संदेश



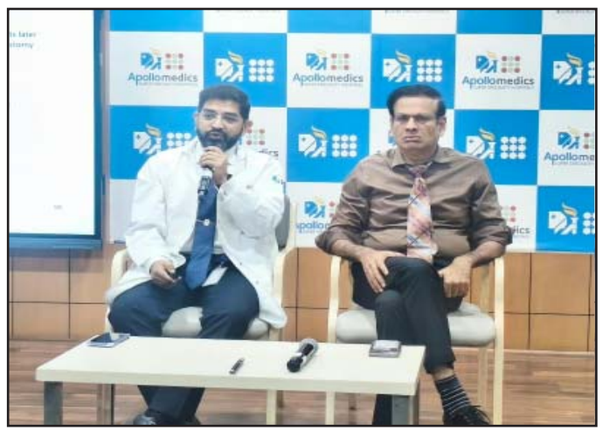
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। लखनऊ पब्लिक कॉलेज, ए ब्लॉक राजाजीपुरम का वार्षिकोत्सव 'माइंडस्केप– मनन महोत्सव' एस.पी. लाइसीयम परिसर, बी ब्लॉक में आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक चेतना के अनूठे संगम के रूप में संपन्न हुआ। डायरेक्टर नेहा सिंह ने चेयरमैन, सांसद डॉ. एस.पी. सिंह का भाषण पढ़ा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि गणों के रूप में एडिटर–एट–लार्ज स्वाति श्रीवास्तव, व शिक्षाविद मार्क बेटरिप सहित लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों की प्रधानाचार्याएं उपस्थित रहीं। समारोह में आध्यात्मिकता, मानवीय मूल्यों और जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर विद्यार्थियों ने प्रभावशाली प्रस्तुतियां दीं। बच्चों द्वारा प्रस्तुत शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक जूलियस सीजर बहुत ही शानदार रहा। इस अवसर पर आई.सी.एस.ई.के 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। उनके अभिभावकों को शॉल एवं पौधे भेंट किए गए, वहीं विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक–शिक्षिकाओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में श्कबीर ––वन ह्यूमैनिटी', 'इबादत', 'आनंदा..' और 'डिल्यूजन ऑफ लिबर्टी' सहित विभिन्न विषयों पर आधारित प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने आध्यात्मिक चेतना, मानवीय संवेदना, आत्मविश्वास और सकारात्मक जीवन–दृष्टि का संदेश दिया। प्रधानाचार्या भारती गोसाई ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

भारत में पहली बार एक ही रोबोटिक सर्जरी में दो अलग-अलग किडनी समस्याओं का इलाज, सात साल की बच्ची को मिली राहत

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ।अपोलोमेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ की यूरोलॉजी टीम ने भारत में पहली बार एक ही रोबोटिक सर्जिकल सत्र में सात साल की बच्ची की दोनों किडनियों से जुड़ी दो अलग–अलग जटिल जन्मजात समस्याओं का सफलतापूर्वक इलाज करने की उपलब्धि हासिल की है। बच्ची की दाईं किडनी में पेल्वियूरेटेरिक जंक्शन यानी पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन था। इस समस्या में किडनी से पेशाब के बहाव में रुकावट आती है। वहीं, बाईं किडनी में ग्रेड–फोर वेसिकोयूरेटेरिक रिफ्लक्स यानी वीयूआर की समस्या थी। इसमें पेशाब मूत्राशय से वापस किडनी की ओर जाने लगता है। यह सर्जरी डॉ. गिवी गौरव, एसोसिएट डायरेक्टर एवं यूनिट हेड, यूरोलॉजी, यूरो–ऑन्कोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट के नेतृत्व में की गई। बच्ची को दो से तीन साल की उम्र से बार–बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई की शिकायत थी। अलग–अलग जगहों पर इलाज कराने के बावजूद संक्रमण बार–बार हो रहा था। बाद में बच्ची को पेट के दाईं ओर और फ्लैंक यानी कमर के पास दर्द के साथ मतली की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे अपोलोमेडिक्स लाया गया। विस्तृत जांच में दाईं किडनी में पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन के साथ एक लोअर–पोल क्रॉसिंग वेसल भी पाया गया। इसका मतलब है कि किडनी के निचले हिस्से के पास मौजूद एक रक्त वाहिका पेशाब के बहाव में रुकावट पैदा कर रही थी। दूसरी ओर, एमसीयूजी जांच में बाईं किडनी में ग्रेड–फोर वीआर की पुष्टि हुई। यह पेशाब के वापस किडनी की ओर जाने की गंभीर समस्या है। डीटीपीए जांच में पता चला कि दाईं किडनी लगभग 40 प्रतिशत और बाईं किडनी लगभग 60 प्रतिशत काम कर रही थी। डॉक्टरों के सामने चुनौती यह थी कि बेहतर काम कर रही बाईं किडनी में भी गंभीर रिफ्लक्स के साथ बार–बार संक्रमण का इतिहास था, जबकि दाईं किडनी में पेशाब के बहाव की महत्वपूर्ण रुकावट थी। दोनों किडनियों की समस्याएं अलग–अलग थीं और उनके इलाज के लिए दो अलग–अलग सर्जिकल प्रक्रियाओं की जरूरत थी। इसलिए डॉक्टरों ने दोनों का इलाज एक ही सर्जिकल सत्र में करने का निर्णय लिया। रोबोटिक सर्जरी के दौरान सबसे पहले दाईं किडनी की रुकावट दूर करने के लिए एंडरसन–हाइन्स पाइलोप्लास्टी की गई। इस प्रक्रिया में रुकावट वाले पीयूजे हिस्से को अलग करके उसका पुनर्निर्माण किया गया, ताकि पेशाब का बहाव सामान्य हो सके। सर्जरी के दौरान वहां मौजूद क्रॉसिंग वेसल को सुरक्षित रखा गया। साथ ही, किडनी के उस हिस्से को, जहां पेशाब इकट्ठा होता है, रक्त वाहिका के आगे की ओर स्थानांतरित किया गया। इससे रुकावट को ठीक करने में मदद मिली। इसके बाद रोबोटिक सिस्टम को अनडॉक किया गया और बच्ची की सर्जिकल पोजिशन बदली गई, ताकि दूसरी किडनी का इलाज किया जा सके। इस प्रक्रिया के लिए पेट में नया पोर्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले से मौजूद लेफ्ट इलियक फोसा यानी पेट के निचले बाईं ओर मौजूद पोर्ट का आकार पांच मिलीमीटर से बढ़ाकर आठ मिलीमीटर किया गया। इसके बाद रोबोटिक सिस्टम को दोबारा डॉक किया गया। दूसरी प्रक्रिया में बाईं किडनी की समस्या ठीक करने के लिए एक्स्ट्रावेसिकल यूरेटेरिक रीइम्प्लांटेशन किया गया। इसमें मूत्रवाहिनी को मूत्राशय से दोबारा इस तरह जोड़ा जाता है कि पेशाब वापस किडनी की ओर न जा सके। इस प्रक्रिया के जरिए बाईं किडनी में मौजूद ग्रेड–फोर रिफ्लक्स का उपचार किया गया। पूरी सर्जरी पांच पोर्ट साइट्स के जरिए एक ही लगातार रोबोटिक सर्जिकल सत्र में पूरी की गई। किसी अतिरिक्त पोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। प्रक्रिया के बीच रोबोटिक सिस्टम का री–रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना पड़ा। सर्जरी का कुल कंसोल टाइम लगभग 323 मिनट रहा, जिसमें 261 मिनट तक सर्जिकल उपकरण सक्रिय रहे। सर्जरी के दौरान लगभग 50 मिलीलीटर खून निकला। प्रक्रिया को ओपन सर्जरी में बदलने की जरूरत नहीं पड़ी और सर्जरी के दौरान कोई जटिलता भी सामने नहीं आई। बच्ची को ऑपरेशन के तीसरे दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सर्जरी के एक महीने बाद हुए फॉलो–अप में बच्ची को कोई नया यूटीआई नहीं हुआ। ऑपरेशन के बाद की अल्ट्रासोनोग्राफी सामान्य रही। डीटीपीए जांच में भी दाईं किडनी में पेशाब के बहाव की कोई रुकावट नहीं पाई गई। एक महीने के फॉलो–अप पर यूरेटेरिक स्टेंट भी सफलतापूर्वक निकाल दिए गए। स्टेंट छोटी ट्यूब होती हैं, जिन्हें



सर्जरी के बाद पेशाब के बहाव को बनाए रखने में मदद के लिए लगाया जाता है। बच्ची की रिकवरी संतोषजनक रही। डॉ. गिवी गौरव ने कहा, "इस मामले की खास बात केवल यह नहीं थी कि दोनों प्रक्रियाएं रोबोट की मदद से की गईं। बच्ची की दोनों किडनियों में अलग–अलग समस्याएं थीं और उनके लिए दो अलग–अलग रिकंस्ट्रक्टिव प्रक्रियाओं की जरूरत थी। चुनौती यह थी कि दोनों समस्याओं का इलाज एक ही एनेस्थीसिया और एक ही रोबोटिक सर्जिकल सत्र में सुरक्षित तरीके से किया जाए, वह भी पेट में अतिरिक्त सर्जिकल एक्सेस बनाए बिना।" उन्होंने कहा, "उपलब्ध प्रकाशित मेडिकल साहित्य में हमें इस विशेष संयोजन का पहले कोई विवरण नहीं मिला। इसमें एक तरफ पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए रोबोटिक पाइलोप्लास्टी और दूसरी तरफ गंभीर वीआर के लिए उसी समय यूरेटेरिक रीइम्प्लांटेशन किया गया। इसलिए यह क्लिनिकल और तकनीकी दृष्टि से एक असामान्य रोबोटिक रिकंस्ट्रक्शन प्रक्रिया है।" यह सर्जरी भारत में अपनी तरह की पहली रोबोटिक रिकंस्ट्रक्टिव प्रक्रिया है। इसमें दोनों किडनियों की अलग–अलग जन्मजात समस्याओं के लिए दो अलग–अलग सर्जिकल प्रक्रियाएं एक ही रोबोटिक सर्जिकल सत्र में पूरी की गईं। अपोलोमेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के एमडी एवं सीईओ डॉ. मयंक सोमानी ने इस उपलब्धि पर कहा, "बच्चों में जन्मजात यूरिनरी ट्रैक्ट संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और विशेषज्ञों से इलाज कराना बेहद महत्वपूर्ण है। इस मामले में टीम ने दोनों किडनियों की अलग–अलग समस्याओं का एक ही मिनिमली इनवेसिव रोबोटिक प्रक्रिया में उपचार किया। यह अपोलोमेडिक्स में जटिल रोबोटिक यूरोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन के लिए उपलब्ध विभिन्न विशेषज्ञताओं और टीम के अनुभव को दर्शाता है।" सर्जिकल टीम इस मामले को विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जरी की बैठक में प्रस्तुत करने और मेडिकल साहित्य में प्रकाशित करने की तैयारी कर रही है।

पूर्वांचल युवा महोत्सव 2026 में सहभागिता हेतु ऑडिशन प्रारम्भ



ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। पूर्वांचल एवं जनपद के नवोदित कलाकारों में अत्यधिक लोकप्रिय पूर्वांचल युवा महोत्सव 2026 में सहभागिता हेतु कलाकारों के चयन हेतु बी आर पी इंटर कालेज के मैदान के सभागार में आयोजित ऑडिशन का पूर्वांचल युवा महोत्सव के संरक्षक द्वय प्रोफेसर समर बहादुर सिंह (पूर्व प्राचार्य, टी डी कालेज) एवं प्रोफेसर अजय कुमार दुबे (बी.एड.विभाग,टी डी कालेज) तथा डॉ प्रमोद कुमार श्रीवास्तव (प्रधानाचार्य) बी आर पी इंटर कालेज द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण द्वारा प्रारंभ हुआ । प्रोफेसर समर बहादुर सिंह ने नवोदित कलाकारों हेतु विशिष्ट अवसर बताते हुए सहभागिता का आह्वान किया ।ऑडिशन में कार्यकरिणी ,पदाधिकारी संजय सिंह, रेखा सिंह, निशांत सिंह भोलू, राखी सिंह, किरण सिंह, दिव्या सिंह, लक्ष्मी, मयंक , राजू शम्स अब्बास, संकल्प सिंह, शहनाज,विक्रांत राय , बच्चा सिंह, महेंद्र मौर्य, आदि ने अपने महत्वपूर्ण विचार और सुझाव प्रदान किये। 'पूर्वांचल युवा महोत्सव के अध्यक्ष डॉ दिनेश कुमार तिवारी ने अवगत कराया कि जनपद ही नहीं वरन पूर्वांचल तथा प्रदेश के नवोदित कलाकारों हेतु पूर्वांचल युवा महोत्सव 17, 18एवं 19 नवंबर को बीआर पी इंटर कॉलेज के मैदान में सम्पन्न होगा। कलाकारों के चयन हेतु पूर्वांचल ही नहीं वरन प्रदेश के विभिन्न जनपदों के कलाकार बी आर पी इण्टर कालेज मैदान के सभागार में 3, 4 एवं 5 नवम्बर को आयोजित ऑडिशन (प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक) में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा कर सहभागिता कर सकते हैं । पूर्वांचल युवा महोत्सव ऑडिशन में ससमय सहभागिता करना अनिवार्य है। महामंत्री निवेदिता राय ने बताया कि पूर्वांचल युवा महोत्सव जनपद जौनपुर का ही नहीं वरन पूर्वांचल से जुड़े हुए विभिन्न जनपदों के नवोदित कलाकारों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मंच जिसमें नृत्य, गायन, वादन, मेहंदी प्रतियोगिता, क्राफ्ट, मिमिक्री, कविता पाठ आदि का आयोजन होना है। संचालन अपूर्वा दुबे तथा आभार उपेंद्र कुमार मिश्र ने किया ऑडिशन का कार्यक्रम देर शाम तक चलता रहा।

मजदूरों के अधिकार, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के लिए सपा मजदूर सभा ने रखा रोडमैप



ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में समाजवादी पार्टी एवं समाजवादी मजदूर सभा के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को मजदूरों, कामगारों और श्रमिकों के अधिकारों एवं सम्मान को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसमें पूर्व एमएलसी शशांक यादव ने मजदूरों के हितों के लिए समाजवादी पार्टी का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। शशांक यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण मजदूरों, कामगारों और गरीब परिवारों का जीवन लगातार कठिन होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी मजदूरों के सम्मान, अधिकार, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर न्यूनतम वेतन का स्थायी निर्धारण, रोजगार की गारंटी और संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी। उन्होंने मजदूरों के लिए राशन, आवास, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, मनरेगा में रोजगार की गारंटी तथा छोटे उद्योगों और कामगारों को आर्थिक सहायता देने को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि मजदूर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके श्रम और योगदान के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। इस दौरान सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बयान पर भी उन्होंने तंज कसा। शशांक यादव ने कहा कि जब सरकार में शामिल लोग खुद को गुंडा बता रहे हैं और गुंडागर्दी खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो इसका जवाब क्या दिया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में गुंडागर्दी होने का समाजवादी पार्टी जो आरोप लगाती रही है, राजभर के बयान से वह बात खुद साबित होती है। लखीमपुर खीरी में एमएलसी चुनाव को लेकर राजभर के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पढ़े–लिखे लोगों का चुनाव है और बाकी जनता उनके साथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में मजदूरों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं और वंचित वर्गों के हितों की अनदेखी हो रही है। समाजवादी पार्टी इनके अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं, उनके सुख-दुख में सदैव साथ खड़ी रहेगी पार्टी- हंसराज विश्वकर्मा

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर।, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा सोमवार को मड़ियाहूं क्षेत्र के रामपुर नदी गांव पहुंचे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता आशुतोष सिंह के चाचा एवं गुलाब सिंह के बड़े भाई शिक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मंत्री ने दिवंगत शिक्षक के आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद



शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और इस दुख की घड़ी में हर संभव साथ देने का भरोसा दिया। इस दौरान हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं। कार्यकर्ताओं के मान–सम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर आंच नहीं आने देगी और उनके सुख–दुख में सदैव साथ खड़ी रहेगी। इस अवसर पर विनीत सेठ सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने बीएचयू रवाना हुई पूर्वांचल विश्वविद्यालय की टीम



ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की पुरुष हैंडबॉल टीम मंगलवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी में आयोजित होने वाली पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए रवाना हुई। विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कुलपति ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल शारीरिक सुदृढ़ता के साथ अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का विकास करते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि विश्वविद्यालय की टीम अपनी मेहनत और खेल कौशल के दम पर प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेगी। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। टीम का नेतृत्व कप्तान कार्तिक यादव कर रहे हैं। टीम के कोच रंजन श्रीवास्तव और मैनेजर डॉ. अखिलेश गौतम हैं। इस अवसर पर प्रो. मनोज मिश्र, प्रो. प्रमोद यादव, प्रो. अविनाश पाथर्डिकर, डॉ. मनीष प्रताप सिंह, जय सिंह सहित विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।

राम–केवट संवाद ने दर्शकों को किया भाव–विभोर

जौनपुर । सिरकोनी ब्लॉक के सलखापुर कजगांव में मौनी बाबा रामलीला समिति के तत्वावधान में आयोजित 80 वर्ष पुरानी रामलीला में रविवार की रात राम–केवट संवाद, मारीच–सीता हरण तथा राम–सुग्रीव मित्रता का भावपूर्ण मंचन किया गया। भगवान राम और केवट के बीच हुए संवाद ने दर्शकों को भाव–विभोर कर दिया। पूरा पंडाल जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा।रामलीला का शुभारंभ मुख्य अतिथि समाजसेवी सुरेंद्र सिंह सेठ और पूर्व प्रधान रणंजय सिंह संजय ने फीता काटकर तथा भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की आरती उतारकर किया। इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह सेठ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।मंचन के दौरान वनवास के समय भगवान राम के नदी पार करने के प्रसंग को जीवंत किया गया। केवट ने प्रभु राम को पहचानने के बाद बिना उनके चरण पखारे नाव पर बैठाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि प्रभु के चरणों के स्पर्श से कहीं उसकी नाव भी पत्थर से नारी बन गई तो उसका जीवन–यापन कैसे होगा। इसके बाद भगवान राम की सहमति से केवट ने उनके चरण पखारे और उन्हें नाव पर बैठाकर नदी पार कराई। इस दौरान श्मांगी नाव न केवट आना, कहहुं तुम्हारा मरम न हम जानाश् के संवाद ने दर्शकों को भावुक कर दिया।इसके बाद रावण द्वारा माता सीता के हरण और राम–सुग्रीव मित्रता के प्रसंग का मंचन हुआ। कलाकारों के सजीव अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा।रामलीला का संचालन राजकमल सिंह ने किया। इस मौके पर समिति के प्रबंधक एवं डायरेक्टर संत प्रकाश धुरंधर सिंह, ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार गौतम पप्पू, पत्रकार दीपक श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

टीडी कालेज की छात्राओं को मिला प्रथम स्थान

जौनपुर। प्रयागराज में मंगलवार को आयोजित प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय रोल प्ले प्रतियोगिता में तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज की छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। प्रदेश के सभी मंडलों की टीमों के बीच हुई इस प्रतियोगिता में विद्यालय की छात्राओं ने वाराणसी मंडल की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश स्तर पर जीत का परचम लहराया।प्रतियोगिता में विद्यालय की छात्राएं काशिश पाण्डेय, जान्हवी वर्मा, वैष्णवी चौरसिया एवं स्वदीपिका सिंह ने प्रतिभाग किया। छात्राओं की इस शानदार उपलब्धि से वाराणसी मंडल के साथ ही विद्यालय का नाम पूरे प्रदेश में रोशन हुआ। छात्राओं को प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराने एवं उनकी तैयारी में डॉ. मंजू सिंह तथा श्रीमती सरिथा सिंह का विशेष योगदान रहा।

सीसी रोड़ निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप

जौनपुर। नगर पंचायत कजगांव के नगर वासियों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर नगर पंचायत कजगाँव के वार्ड संख्या तीन माधोपट्टी में मानक के विपरीत बनाये जा रहे सीसी रोड निर्माण कार्य में मानक की अनदेखी व भारी अनियमितत की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग किया है। शिकायती पत्र द्वारा डीएम को नगरवासियों द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत कजगाँव द्वारा वार्ड संख्या 3 में मझलेपुर छोटी मस्जिद के पास से माधोपट्टी सरहद तक सी.सी.रोड़ का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसके साइड वाल में घटिया किस्म के ईंट एवं सीसी रोड में घटिया किस्म के निर्माण सामग्री का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। सीसी रोड के साईड वाल के नाम पर दो ईंट व सीसी रोड कार्य में नाम मात्र की गिट्टी डालकर उसकी कुटाई कराये बगैर कार्य रोड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शिकायत के बावजूद अधिशासी अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से स्वतः स्पष्ट है कि उक्त घटिया निर्माण कार्य में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अध्यक्ष तथा ठेकेदार की मिलीभगत से हो रहा है। ताकि सरकारी खजाने से धन अर्जित हो सके। सीसीरोड़ के नीचे जल निकासी हेतु सीवर व जल निगम की पाईप बिछी हुई है जिसमें एकाध लोगों ने निर्माण कार्य से पहले कनेक्शन लिया है। शेप मकानो में कोई कनेक्शन ठेकेदार और जिम्मेदार द्वारा नही कराया गया जिससे जल निकासी व पेय जल की समस्या से आस–पास के लोगो को काफी दिक्कत व परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार की नीतियों से मजदूरों जा जीवन कठिन- षषांक

जौनपुर। समाजवादी पार्टी एवं समाजवादी मजदूर सभा के संयुक्त तत्वावधान में मजदूरों, कामगारों एवं श्रमिकों के अधिकारों और सम्मान के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व एमएलसी शशांक यादव, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी श्री रामगोपाल पूरी तथा मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री धन्नीलाल श्रमिक ने मजदूरों के हितार्थ समाजवादी पार्टी का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया। नेताओं ने वर्तमान भाजपा सरकार की मजदूर विरोधी मानसिकता को उजागर करते हुए कहा कि सरकार की नीतियों से मजदूरों, कामगारों एवं गरीब परिवारों का जीवन लगातार कठिन होता जा रहा है।नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी मजदूरों के सम्मान, अधिकार, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समाजवादी सरकार बनने पर न्यूनतम वेतन का स्थायी निर्धारण, मजदूरों को रोजगार की गारंटी, संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में ठोस पहल, मजदूरों के लिए राशन एवं आवास की व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा, मनरेगा में रोजगार की गारंटी तथा छोटे उद्योगों एवं कामगारों को आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।उन्होंने कहा कि मजदूर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके श्रम और योगदान के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है।

सरकारी गोशालाओं मे संरक्षित बेसहारा गोवंश के लिए किसानों से सीधे हरा चारा खरीदेगा प्रशासन



अयोध्या।जिले के सरकारी गोशालाओं में संरक्षित बेसहारा गोवंश को अब पूरे वर्ष हरा चारा उपलब्ध कराने की तैयारी है।इसके लिए पशुपालन विभाग आसपास के किसानों से सीधे हरा चारा खरीदेगा।इस बात की जानकारी देते हुए सीवीओ डॉ इंद्रदेव ने बताया कि इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी होगी।वहीं गोवंश को भी पौष्टिक चारा मिल सकेगा।बताया कि अभी तक गोशालाओं में चारा और भूसे की व्यवस्था विभाग की ओर से की जाती थी।अब इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए किसानों से सीधे अनुबंध किया जा रहा है।बताया कि जिले के रुदौली सहित सभी ब्लॉक क्षेत्रों में अब तक 73 किसानों से अनुबंध किया जा चुका है।सभी किसान अपनी उपलब्धता के अनुसार पूरे वर्ष में उगाई जाने वाली चारा फसलों की जानकारी देंगे।चारा काटकर गोशालाओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी किसानों की होगी।बताया कि इसके बदले भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में चेक के माध्यम से किया जाएगा। बताया कि वह रुदौली सहित कई ब्लॉकों में स्थित गोशालाओं का निरीक्षण भी किया। बताया कि इसके साथ ही साथ सरकार नेपियर घास की खेती को भी बढ़ावा दे रही है। इस घास की खासियत है कि एक बार लगाने के बाद छह से सात वर्ष तक हरा चारा प्राप्त किया जा सकता है।पशुओ के लिए यह पचने में आसान और प्रोटीन से भरपूर होंगी।

दीपावली पर पटाखों की जगह करे आतिशबाजी का प्रयोग - डॉ गौरव श्रीवास्तव



अयोध्या। दीपावली त्योहार पर पटाखे की जगह अधिक से अधिक कम प्रदूषण वाले आतिशबाजी का प्रयोग लोग करे। कोशिश यही रहे इस पर्व पर पटाखों से परहेज करें। यह बात शहर के प्रसिद्ध नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव ने कही। बताया कि पटाखों से निकलने वाला तेज शोर खासकर कान पर ज्यादा प्रभाव डालता है और कभी–कभी कुछ मामले ऐसे भी आते हैं सुनने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। बताया कि इससे हम लोगों को सावधानी बरतनी होगी। अगर कोई पटाखा छोड़ता भी है तो अधिक से अधिक 60 डेसीबल उसकी आवाज होनी चाहिए उससे अधिक की आवाज खुद तथा आसपास के लोगों को प्रभावित करती है।तेज पटाखों की ध्वनि कान के भीतरी हिस्से की संवेदनशील कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है।इससे सुनने की क्षमता कम होने, कान में घंटी या सीटी बजने और अस्थायी अथवा स्थायी बहरापन होने का खतरा रहता है।उन्होंने कहा कि बच्चों को विशेष रूप से तेज आवाज वाले पटाखों से दूर रखें।वही आतिशबाजी के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखें और पटाखों को कान के पास बिल्कुल न जलाएं।कहा कि पटाखे फूटने के बाद कान में सीटी बजने, आवाज कम सुनाई देने या कान बंद महसूस होने जैसी परेशानी को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए।ऐसी स्थिति में तत्काल ईएनटी विशेषज्ञ से परामर्श लेना जरूरी है।उन्होंने लोगों से अपील की कि दीपावली की खुशियां कम आवाज और सुरक्षित आतिशबाजी के साथ मनाएं।

नवंबर से फरवरी तक छात्रों को मिलेगा हलवा व उपमा

अयोध्या।ठंड के मौसम में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ अब सूजी का मीठा हलवा और नमकीन उपमा भी परोसा जाएगा। इस बात की जानकारी बीएसए लालचंद ने दी। बताया कि प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत शुरू की जा रही इस व्यवस्था का लाभ इसी माह नवंबर से मिलेगा।इसके लिए विभाग की ओर से दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।मालूम हो इसके पहले सर्दियों के मौसम में छात्रों को गुड़ से बनी चिक्की, गजक और रामदाना के लड्डू वितरित किए जाते रहे हैं।इस बार इनकी जगह सूजी से तैयार हलवा और नमकीन उपमा देने की व्यवस्था की गई है।इसके पीछे बच्चों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने की मंशा है। बताया कि नवंबर से फरवरी 2027 के तीसरे सप्ताह तक इस व्यवस्था का संचालन किया जाएगा।प्रत्येक शुक्रवार को बच्चों को मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त हलवा या उपमा दिया जाएगा।महीने के पहले और तीसरे सप्ताह में मीठा हलवा तथा दूसरे, चौथे और पांचवें सप्ताह में नमकीन उपमा वितरित होगा।बताया कि अगर किसी शुक्रवार को अवकाश होता है तो अगले कार्यदिवस में इसका वितरण किया जाएगा।प्रत्येक छात्रों के लिए न्यूनतम 30 ग्राम सूजी निर्धारित की गई है।विद्यालयों में रसोइयों द्वारा हलवा और उपमा तैयार कराया जाएगा।खाद्य सामग्री की गुणवत्ता,एफएसएसएआई मानकों और एक्सपायरी डेट का ध्यान रखने के साथ वितरण का रिकॉर्ड और फोटोग्राफी भी कराई जाएगी।

'विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बहुरावां एवं नरसड़ा में 'खेत बचाओ' कार्यक्रम, किसानों को मिली उन्नत तकनीक की जानकारी'



ब्यूरो चीफ – आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुल्तानपुर।' विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत विकासखंड बल्दीराय के ग्राम बहुरावां एवं नरसड़ा में 'खेत बचाओ' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र बरासिन, सुल्तानपुर के शस्य वैज्ञानिक डॉ. पंकज कुमार सिंह ने किसानों को रबी फसलों के बेहतर उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण और खेती की लागत कम करने के गुर बताए। डॉ. सिंह ने कहा कि किसान भाई फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका प्रबंधन करें। इससे मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ता है, नमी बनी रहती है और मिट्टी की संरचना सुधरती है। उन्होंने मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक प्रयोग, प्रमाणित बीज, बीजोपचार और समय से बुवाई पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल करने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। गन्ने के साथ सहफसली खेती से किसान अतिरिक्त आय ले सकते हैं। प्राकृतिक खेती के तहत जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत और आच्छादन के फायदे बताए। सहायक विकास अधिकारी (कृषि) डॉ. पवन कुमार ने कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी दी और किसानों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। इस दौरान बीज गोदाम प्रभारी अशोक कुमार वर्माऔर वरिष्ठ प्राविधिक सहायक जगजीवन ने भी किसानों को जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

'जिलाधिकारी ने जनसुनवाई में सुनीं 86 शिकायतें'



'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' मंगलवार को जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। इस दौरान कुल 86 शिकायतें प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी ने शिकायत कर्ताओं की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा प्रत्येक शिकायत का निष्पक्षता से परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसामान्य की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए, जिससे लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक राजेन्द्र कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

शहर से लेकर गांव तक कई कोचिंग व स्कूल शिक्षा विभाग के रहमोकरम से बिना पंजीकरण व मान्यता के संचालित

अयोध्या।शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सैकड़ों कोचिंग संस्थान संचालित होने की बात सामने आ रही है।इनमें कई संस्थान बिना पंजीकरण के ही विद्यार्थियों और अभिभावकों से मोटी फीस वसूल रहे हैं।वही कुछ कोचिंग संचालक तो कोचिंग की आड़ में विद्यालय तक चला रहे हैं।देखा जाये तो शहर के नियावां, रिकाबगंज, साहबगंज, हैदरगंज, वजीरगंज, देवकाली, नाका और सिविल लाइंस सहित प्रमुख इलाकों में ऐसे संस्थानों की भरमार है।वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बीकापुर, तारुन, जाना बाजार, मिल्कीपुर, गोसाईगंज और रुदौली सहित विभिन्न बाजारों में भी इनका संचालन हो रहा है।ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर है।आरोप है कि कक्षा आठ तक मान्यता प्राप्त कुछ विद्यालयों में निर्धारित मान्यता से अधिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।इसके बावजूद विभागीय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा का भरोसा देकर मोटी फीस वसूलने वाले इन संस्थानों की गुणवत्ता और सुविधाओं की जांच भी सवालों के घेरे में है।हैरानी की बात यह है कि शिक्षा विभाग समय–समय पर जांच समितियों का गठन तो करता है, लेकिन अवैध संस्थानों के संचालन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।ऐसे में सवाल उठता है कि जब विभाग के पास केवल तीन दर्जन संस्थानों का पंजीकरण है तो बाकी संस्थान किसकी निगरानी में चल रहे हैं?क्या विभाग को इनकी जानकारी नहीं है या फिर कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है?

उप निरीक्षक प्रिया ने जिला महिला चिकित्सालय सहित अन्य जगहों पर महिलाओ व बेटियों को किया जागरुक



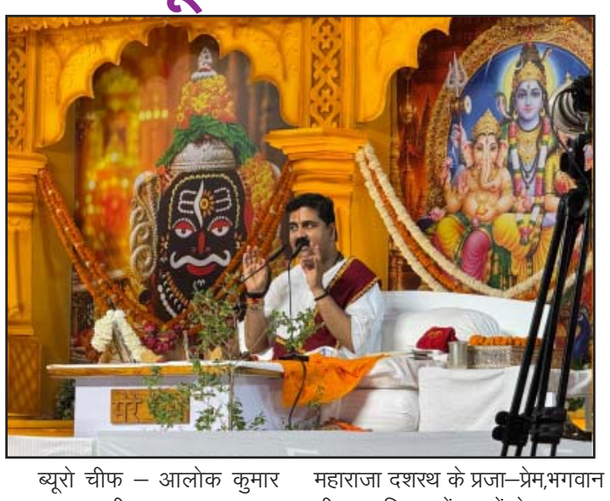
(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।महिला उप निरीक्षक प्रिया ने पीआरडी किरन व माधुरी रिकाबगंज चौराहा, जिला महिला चिकित्सालय व अन्य जगहों पर जाकर महिलाओं व बेटियों को जागरुक किया।इस मौके पर उन्होंने जिला महिला चिकित्सालय व रिकाबगंज आई महिलाओ, नर्सो, व परिजनों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में बैनर पंपलेट पोस्टर के माध्यम से समझाया।उन्होंने बालिकाओं एवं महिलाओं को विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सुकन्या योजना, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान तथा महिला सुरक्षा एवं अधिकारों की जानकारी दी।इस दौरान 1090, 112, 181, 1076, 1098 एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में जागरूक करते हुए किसी भी समस्या या उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता लेने की अपील की गई।

सीएमओ ने खोह व भौंरी पीएचसी में आरोग्य मेले का किया निरीक्षण

बांदा, (संवाददाता)। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रविवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएमओ डॉ महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने पीएचसी खोह के मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि केंद्र पर उपलब्ध दवाओं को व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। सीएमओ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान तक 13 मरीज देखे जा चुके थे। चार मरीजों के जांच हो चुकी थी। पीएचसी के डॉ विवेक और समस्त स्टाफ उपस्थित थे। सीएमओ ने ओपीडी और जांच संबंधी, व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। सभी चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस पहनकर ही ड्यूटी करने की सख्त चेतावनी दी और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। अस्पताल परिसर की साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया और इसे बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होने चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि मरीजों को बाहर से दवाएं न लिखी जाएं। स्वास्थ्य केंद्र पर समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं सुगम स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने तथा मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

'राम नाम की लूट मची है लूट सके तो लूट लो – राजन जी महराज'



ब्यूरो चीफ – आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुल्तानपु। बल्दीराय ब्लॉक के सिंहनी स्थित अमृत गार्डन में चल रही श्रीराम कथा के चौथे दिन सोमवार को श्रद्धालुओं का जनसैलाब इस प्रकार से उमड़ पड़ा की पूरा पंडाल भर गया। यही नही अगली पंथ में बैठकर कथा सुनने के लिए लोग इस तरह आतुर हो रहे हैं कि 12रू00 से ही पंडाल में पहुंचकर लोग बैठ जाते हैं।अंतरराष्ट्रीय कथा वाचक राजन जी महाराज की अमृत वाणी सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रोता महराज के दर्शन को आतुर रहते है।ब्लॉक प्रमुख शिवकुमार सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह ने सपरिवार व्यासपीठ का विधिवत पूजन कर प्रभु श्रीराम और हनुमान जी महाराज से क्षेत्रवासियों की सुख–समृद्धि की कामना की।कथा के दौरान राजन जी महाराज ने महाराजा दशरथ के प्रजा–प्रेम,भगवान श्रीराम सहित चारों भाइयों के नामकरण और भगवान विष्णु–वृंदा–जालंधर के पौराणिक प्रसंगों का वर्णन किया।महराज जी ने कहा कि धन–दौलत ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। सद्कर्म, परोपकार और प्रभु भक्ति ही जीवन को सार्थक बनाते हैं।महाराज के लोकप्रिय भजन श्राजा जी खजानवां दे दाश पर श्रद्धालु नाचने–झूमने लगे।जय श्री सीताराम के जयघोष से पूरा पंडाल राममय हो गया । आगे उन्होने कहा कि रामनाम की लूट मची है लूट सके तो लूट लो श्रीराम जी जगत के माता पिता है। वे सब को सुख दे रहे है। अगे श्री महराज ने कहा की भगवान शंकर जी कहते है जो भगवान श्री राम के चरण मे रहता है उसे सब सुख मिलता है। श्री महराज ने कहा कि मानस है। अमृत की धारा इसको पीता है। संसारा भजन के माध्यम से उपस्थित लोगों को कथा का अमृत रस पिलाते हुए महराज ने कहा कि राम नाम भज प्यारे नही पछताएगा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि आज यह भी देखा जा रहा है कि माता–पिता परिवार वी धर्म के प्रति आस्था विश्वास कम हो रहा है इसके लिए । हम सब स्वयं जिम्मेदार हैं आज छोटे–छोटे बच्चों को लोग हॉस्टल में भेज दे रहे हैं उनकी फरवरी माता के द्वारा नहीं हो पा रही है इस कारण से बच्चों में माता के प्रति इसने काम होता जा रहा है । कार्यक्रम में राज्य सभा सांसद रामाराव,विधायक राज बाबू उपाध्याय, भाजपा नेता रामचंद्र मिश्रा, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य विकास शुक्ला,पूर्व भाजपा जिला मंत्री मुकेश अग्रहरी, प्रधान अमन सोनी, पूर्व प्रधान महेश जयसवाल , प्रधान राजेश दूबे , प्रधान जय प्रकाश मिश्र , भाजपा मण्डल महामंत्री अमन वर्मा नरेन्द्र अग्रहरि , घनश्याम तिवारी , मिस्त्री रामलाल वर्मा ,राहुल वर्मा, गीतांजलि सिंह, अभिराज सिंह, दीपांजलि सिंह, हर्ष सिंह, जिला पंचायत सदस्य रामशंकर यादव, वरिष्ठ पत्रकार प्रभात सिंह, पूर्व प्रधान किरन सिंह हलियापुर, आर पी शुक्ला , श्याम प्रति ,बाबा योगराज , प्रधान प्रतिनिधि बृजेंद्र तिवारी बहादुर,भाजपा नेता अवधेश दूबे, एडीओ पंचायत दयावंत सिंह और मनोज यादव,ठेकेदार वेद अग्रहरि,अरविंद सिंह बबलू,ठेकेदार अभिमन्यु मिश्र,राम कृष्ण शुक्ला ,ठेकेदार तौसीफ खान , बीरेन्द्र कुमार मिश्र , मनोज मिश्र , सहित हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे।

एसी कमरों से निकलने वाले आदेशों की जमीन पर ऐसी लैंडिग कि सात कर्मचारी घायल

सुल्तानपुर, (संवाददाता)। चुनहा स्थित जीडी गोयनका स्कूल में जनगणना प्रशिक्षण के दौरान लिफ्ट हादसे में सात सरकारी कर्मचारियों के घायल होने की घटना ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसे अब किसी सरकारी फाइल, प्रेस नोट या जांच समिति के नीचे दबाना आसान नहीं होगा। आखिर सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजने से पहले यह देखना किसकी जिम्मेदारी थी कि जिस भवन में उन्हें भेजा जा रहा है, वहां उनकी जान सुरक्षित भी है या नहीं। कागजों पर व्यवस्था चाक–चौबंद रही होगी। आदेश भी बाकायदा निकला होगा। ड्यूटी भी लग गई होगी। लेकिन जैसे ही लिफ्ट नीचे गई, व्यवस्था की विश्वसनीयता भी उसके साथ नीचे जाती दिखाई दी। एसी कमरे में बैठकर सुरक्षा का तापमान नहीं नापा जा सकता। बेसिक शिक्षा विभाग का काम सिर्फ आदेश निकालना नहीं है। शिक्षकों को कहां भेजा जा रहा है, किस परिसर में भेजा जा रहा है और वहां सुरक्षा के न्यूनतम मानक पूरे हैं या नहीं। इन सवालों का जवाब भी प्रशासनिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। लेकिन अगर प्रशिक्षण स्थल की लिफ्ट तक की फिटनेस जांचने की जरूरत महसूस नहीं हुई तो सवाल बनता है क्या विभाग में सुरक्षा का मतलब सिर्फ फाइल पर लगा अनुमोदित का ठप्पा रह गया है। क्योंकि जमीन पर उतरते ही अगर सिस्टम की पहली परीक्षा में ही लिफ्ट फेल हो जाए तो फिर सवाल सिर्फ मशीन का नहीं, मशीनरी का भी है।

ड्यूटी लगाओ संस्कृति में सुरक्षा सुनिश्चित करो कहां गायब है

सरकारी कर्मचारी आदेश का पालन करता है। उसे यह तय करने का अधिकार नहीं होता कि प्रशिक्षण कहां होगा। उसे यह भी तय नहीं करना होता कि भवन सुरक्षित है या नहीं। वह तो आदेश पाकर पहुंचता है। इसलिए जिम्मेदारी उस अधिकारी तंत्र की बनती है जिसने उसे वहां भेजा। ड्यूटी लगाना आसान है, लेकिन ड्यूटी स्थल सुरक्षित बनाना असली प्रशासन है। अब विभाग को बताना चाहिए कि प्रशिक्षण स्थल का चयन किसने किया। लिफ्ट की फिटनेस रिपोर्ट किसने देखी। फायर सेफ्टी और अन्य सुरक्षा मानकों का सत्यापन हुआ या नहीं। दुर्घटना से पहले परिसर का निरीक्षण किस अधिकारी ने किया। अगर निरीक्षण हुआ था तो उसकी रिपोर्ट कहां है। इन सवालों के जवाब जितनी जल्दी आएंगे, उतनी जल्दी विभाग पर उठती उंगलियां भी शांत होंगी।

पिक एंड चूज की शिकायतें भी संयोग नहीं मानकर जांची जाएं

विभागीय ड्यूटियों को लेकर शिक्षकों के बीच यदि लंबे समय से पक्षपात या पिक एंड चूज की शिकायतें हैं तो उन्हें भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कौन छुट्टी के दिन ड्यूटी करता है। किसे बार–बार जिम्मेदारी मिलती है। किसे राहत मिलती है। ड्यूटी आवंटन का आधार क्या है। अगर सब कुछ नियम से हो रहा है तो विभाग के पास रिकॉर्ड होंगे। रिकॉर्ड सामने रखिए, सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन यदि रिकॉर्ड ही सवाल पैदा करते हैं तो फिर जांच भी जरूरी होगी।

जीडी गोयनका परिसर पर भी जवाब चाहिए

यदि इस परिसर को लेकर पहले विभागीय स्तर पर शिकायतें या विवाद रहे हैं, तो यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि उसी स्थान को सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए चुनते समय सुरक्षा मानकों की दोबारा जांच क्यों नहीं की गई। यहां किसी को दोषी घोषित करना उद्देश्य नहीं है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी से जवाब मांगना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अधिकार है। और इस मामले में जवाब सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि जांच कराई जा रही है। सवाल यह है कि जांच पहले क्यों नहीं हुई। अब जांच नहीं, जवाबदेही चाहिए। हादसे के बाद जांच बैठाना प्रशासन की सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इस बार जांच सिर्फ यह न बताए कि लिफ्ट क्यों गिरी। यह भी पता लगाए।

परीक्षा देने रायबरेली जा रहे बेसिक शिक्षा विभाग के लिपिक की सड़क हादसे में मौत

सुल्तानपुर, (संवाददाता)। परीक्षा देने बुलेट से रायबरेली जा रहे अंबेडकरनगर बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात लिपिक की रविवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के सेमरी बाईपास के पास सामने से आ रही टूरिस्ट बस ने उनकी बुलेट में टक्कर मार दी। हेलमेट पहने होने के बावजूद सिर में गंभीर चोट लगने से वह घायल हो गए थे। इलाज के दौरान अंबेडकरनगर में उनकी मौत हो गई। अंबेडकरनगर जिले के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी प्रत्युष वर्मा (22) अकबरपुर स्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बड़े बाबू के पद पर तैनात थे। रविवार को वह बुलेट से परीक्षा देने रायबरेली जा रहे थे। जयसिंहपुर क्षेत्र के नगईपुर गांव के पास सेमरी बाईपास पर पास लेते समय उनकी बाइक सामने से आ रही टूरिस्ट बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्रत्युष सड़क किनारे जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद बस चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची

2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर जदयू की नजर, कार्यकर्ता सम्मेलन में निशांत कुमार ने भरी हुंकार

वाराणसी, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने रविवार को वाराणसी में शक्ति प्रदर्शन किया। राज्यस्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कार्यकर्ताओं से गांव, पंचायत और बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जदयू उत्तर प्रदेश में जनता की आवाज बनेगा। वहीं, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्य देश के लिए मिसाल हैं। सम्मेलन में भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष विजय कुमार राजभर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।